



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/चैत्र 9, 1939

No. 77]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

प्रकरण सं. ओ आई-21/2017

**विषय :** चीन जन. गण., के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ताश के पत्तों" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरूआत।

**सं.14/43/2016-डीजीएडी.—**मै. पार्कसंस ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मै. पार्कसंस कार्टामुंडी प्रा. लि. और मै टी एम प्रिंटर्स प्रा. लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कंपनियां या आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ताश के पत्तों" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की

मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### **विचाराधीन उत्पाद**

3. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद "ताश के पत्ते" है। ताश के पत्ते 52 आयताकार पतले पत्तों का एक पैक होते हैं जो कागज या पीवीसी के बने होते हैं, जिनका आम तौर पर विभिन्न खेलों को खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ताश के पत्तों में संख्याओं का क्रम और उनके एक तरफ डायमंड, हर्ट्स, क्लब, या स्पेड्स होते हैं परंतु दूसरी तरफ एकसमान डिजाइन होता है। 52 ताश के पत्तों के पूरे सेट को एक पैक या एक डैक या एक सेट कहा जा सकता है।
4. पीयूसी का प्रयोग किस्मत और कौशल के विभिन्न खेलों को खेलने में किया जाता है। इनका प्रयोग भ्रम, पत्तों की बाजीगरी, कार्ड के ढांचे, कार्टोमेसी और मेमोरी स्पोर्ट के लिए भी किया जाता है।
5. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के टैरिफ मद 9504 40 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
6. आयात आकड़ों का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस से उपलब्ध कराए गए सौदा वार आयात आकड़ों पर भरोसा किया है।

### **समान वस्तु**

7. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तु और भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित की जा रही और संबद्ध देशों से आयात किया जा रहा विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अंतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

### **घरेलू उद्योग**

8. यह आवेदन मै. पार्कसंस ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मै. पार्कसंस कार्टामुंडी प्रा. लि. और मै टी एम प्रिंटर्स प्रा. लि. द्वारा दायर किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार पूर्वोक्त तीन उत्पादकों के उत्पादन का भारतीय उत्पादन में कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है और भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा यह आवेदन सात घरेलू उत्पादकों अर्थात् जे एम के एंटरप्राइजेज, कगलवाला पैकेजिंग प्रा. लि., एल के एम एंटरप्राइजेज, नंदी प्रिंटर्स प्रा. लि., अजंता प्रिंट आर्ट्स, भतीजा एंटरप्राइजेज और टी एम एंटरप्राइजेज प्रा. लि. द्वारा समर्थित है।

9. प्राधिकारी मानते हैं कि समर्थनकारी घरेलू उत्पादकों के साथ याचिकाकर्ता योग्यता के संबंध में संबंधित नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है और नियम 5(3) की अपेक्षाओं के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को भी पूरा करता है।

### **शामिल देश**

10. वर्तमान जांच में चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में हैं।

### **सामान्य मूल्य**

11. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में किसी विश्वसनीय सूचना के अभाव में संबद्ध देश से सामान्य मूल्य का अनुमान उत्पादन लागत के आधार पर कच्ची सामग्री की लागत, सुविधाओं की लागत और घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों जमा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके विचार करते हुए लगाया गया है।

**निर्यात कीमत**

12. आवेदकों ने भारत में आईबीआईएस द्वारा प्रकाशित सौदा वार आयात आकड़ों के आधार पर चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद की भारत औसत आयात कीमत के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। तथापि, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस से उपलब्ध सौदा-वार आयात आकड़ों की भी जांच की है। समुद्री भाड़े, अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री बीमा, प्रहस्तन प्रभारों और संबद्ध देश में गैर-वापसी योग्य वैट के संबंध में कीमत समायोजनों का दावा किया गया है।

**पाटन मार्जिन**

13. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जो संबद्ध देश के संबंध में पर्याप्त पाटन मार्जिन दर्शाती है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

14. अनुमानित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

**क्षति और कारणात्मक संबंध**

15. आवेदकों ने दावा किया है कि उन्हें वास्तविक क्षति हुई है और उन्होंने आयातों में समग्र रूप से वृद्धि और घरेलू उत्पादन और घरेलू मांग के संबंध में वृद्धि में संबद्ध देश से कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से पाटन के कारण घरेलू उद्योग के बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, मालसूची, लाभ आदि में गिरावट आई है।

16. आवेदकों ने कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के साक्ष्य के रूप में प्रतिकूल कीमत प्रभावों का भी दावा किया है। प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देश से पाटन आयातों के कारण आवेदकों द्वारा उठाई जा रही क्षति के पर्याप्त साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

**जांच अवधि**

17. वर्तमान जाँच के लिए जांच अवधि (पीओआई) अप्रैल 2015 से सितंबर 2016 (18 माह) तक की है। तथापि, क्षति जाँच में अप्रैल 2012 से मार्च 2013, अप्रैल 2013 से मार्च 2014, अप्रैल 2014 से मार्च 2015 और जांच की अवधि (पीओआई) के आकड़ों पर विचार किया जाएगा।

**सूचना प्रस्तुत करना**

18. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं:-

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**भारत सरकार**  
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,**  
**नई दिल्ली- 110001**

20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले पक्षकार को उसका अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

**समय-सीमा**

21. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना इस जाँच शुरुआत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना

प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को **एतद्वारा** सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें। सूचना मूल प्रतियों तथा साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत की जाएं। सूचना मूल प्रतियों और साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है।

### **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

23. यदि उसके किसी भाग के संबंध में 'गोपनीयता' का दावा किया जाता है तो प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

(क). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, पृष्ठ संख्या, सूची, आदि); और

(ख). अगोपनीय रूप में अन्य दूसरा सैट (शीर्षक, पृष्ठ संख्या, सूची, आदि)।

24. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियाँ प्रत्येक के पाँच (5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

25. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

29. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

30. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### **असहयोग**

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2017

**Case No. OI-21/2017**

**Sub:— Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Playing Cards” originating in or exported from China PR.**

1. **No 14/43/2016- DGAD.**—M/s Parksons Graphics Private Limited, M/s. Parksons Cartamundi Private Limited and M/s T M Printers Private Limited (hereinafter referred to as “petitioner companies” or “the applicants”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) have submitted an application for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on the imports of Playing Cards (hereinafter referred to as the subject goods or the Product Under Consideration), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

**Product under consideration**

3. The product under consideration for the purpose of present investigation is ‘Playing Cards’. Playing cards are a pack of 52 rectangular thin cards made of paper or PVC, generally used for playing a variety of games. Playing cards have a sequence of numbers and symbols such as diamonds, hearts, clubs, or spades on the face, but an identical design on the reverse. A complete set of 52 playing cards may be called a pack or a deck or a set.
4. The PUC is used in playing various games of chance and skill. They are also used for illusions, cardistry, building card structures, cartomancy and memory sport.
5. The product under consideration is classified under Tariff item 9504 40 00 of the Custom Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
6. For the purpose of analyzing import data, the Authority has relied upon transaction wise import data available from the DGCIS.

**Like Article**

7. The applicants have claimed that the subject goods being produced by the domestic industry are similar to the subject goods being dumped into India. The applicants have claimed that PUC produced by the applicants and imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as ‘like article’ to the subject goods being imported from the subject country.

**Domestic Industry**

8. The Application has been filed M/s Parksons Graphics Private Limited, M/s. Parksons Cartamundi Private Limited and M/s T M Printers Private Limited. As per the information available on record, the production of the aforesaid three producers accounts for a major proportion of the total domestic production and is more than 50% of Indian production. The Application has also been supported by seven domestic producers namely, J M K Enterprises, Kagalwala Packaging Pvt Ltd, L K M Enterprises, Nandi Printers Pvt Ltd, Ajanta Print Arts, Bhatija Enterprises and T M Enterprises Pvt Ltd.
9. The Authority holds that the petitioner along with supporting domestic producers constitutes an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and satisfies the criteria of standing also in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

**Country involved**

10. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR (referred to as the “subject country”).

**Normal Value**

11. The petitioners have submitted that in absence of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject country, the Normal Value in the subject country have been estimated on the basis of cost of production; taking into account cost of raw material, cost of utilities and conversion cost of domestic industry, duly adjusted on account of selling, general & administration expenses, plus reasonable profit.

**Export Price**

12. The applicants have determined the export price on the basis of weighted average import price for the product under consideration from China PR based on the transaction wise import data available from IBIS in India. However, the Authority has also looked into transaction wise import data available from the DGCIS. Price adjustments have been made on account of Ocean Freight, Inland Freight, Ocean Insurance, Handling Charges and Non-Refundable VAT for the subject country.

**Dumping Margin**

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal values of the subject goods in the subject country are significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.
14. The dumping margin is estimated to be significantly above de minimis.

**Injury and Causal Link**

15. The applicants have claimed that they have suffered material injury and have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping from the subject country in terms of increase in imports in absolute terms and in relation to domestic production and domestic demand. The dumping from the subject country has resulted in deterioration of sales, production, capacity utilization, market share, inventories, profits, etc. of the domestic industry.
16. The applicants have also claimed adverse price effects as evidenced by price undercutting and price underselling. The Authority considers that there is sufficient evidence of ‘injury’ being suffered by the applicants caused by dumped imports of the subject goods from the subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

**Period of Investigation**

17. The period of investigation (POI) for the present investigation is from April 2015 to September, 2016 (18 months ). The injury investigation period will, however, cover the periods April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014-March 2015 and the POI.

**Submission of information**

18. The known exporters in the subject country and its Government through its Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce  
Government of India  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street,  
New Delhi-110001**

20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**Time Limit**

21. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the publication of initiation notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of the publication of initiation notification. The information must be submitted in hard copies as well as in soft copies.

**Submission of information on confidential basis**

23. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
  - i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
  - ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
24. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.
25. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the

substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **Inspection of Public File**

30. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

#### **Non-cooperation**

31. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority